भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4585
जिसका उत्तर 20 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
29 श्रावण, 1947 (शक)

मेक इन इंडिया

4585. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में विशेष रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) क्या इन पहलों के परिणामस्वरूप उक्त राज्य में आईटी उद्योग में रोजगार में उल्लेखनीय सृजन हुआ है;

(ग) महाराष्ट्र में किनने जनजातीय लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है; और

(घ) उक्त राज्य के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य सेवा केंद्रों और स्मार्ट डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) और **(ख):** प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिकी सामान के उत्पादन और निर्यात में अवलोकित की गई उल्लेखनीय वृद्धि निम्नानुसार है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियाँ
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का उत्पादन (₹)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का निर्यात	0.38 लाख करोड़	3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ	2 इकाइयाँ	300 यूनिट	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फ़ोन का उत्पादन (₹)	0.18 लाख करोड़	5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फ़ोन का निर्यात (₹)	0.01 लाख करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फ़ोन (कुल इकाइयों का %)	मांग का 75%	मांग का 0.02%	

यह उपलब्धि पिछले 11 वर्षों में सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों और सुधारों का परिणाम है। इनमें से कुछ उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)
- इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर विनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017

ये सभी पहलें पूरे भारत में हैं और कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इनका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा, कंपनियाँ आपूर्ति श्रृंखला संपर्क, अवसंरचना के समर्थन और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अन्य सुगमता प्रति उपायों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के स्थानों का चयन करती हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) सृजित हुए हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 85 इकाइयों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य में 2 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) और 1 इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना (आईबीपीएस) शुरू की थी, जिसका उद्देश्य पूंजी और परिचालन व्यय के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के रूप में 1 लाख रुपये प्रति सीट तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके बीपीओ/आईटीईएस परिचालनों की स्थापना को प्रोत्साहित करके छोटे शहरों/कस्बों में रोजगार के अवसर पैदा करना और आईटी/आईटीईएस उद्योग का प्रसार करना था। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने वाली इकाइयों को विभिन्न विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए गए, जिनमें महिलाओं और दिव्यांगजनों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल थे। इस योजना के अंतर्गत, देश के 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 93 छोटे शहरों/कस्बों में 227 इकाइयों ने बीपीओ/आईटीईएस परिचालन स्थापित किए और 52,564 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान किए। महाराष्ट्र में, 6 शहरों (औरंगाबाद, भिवंडी, धवलगांव, नागपुर, नासिक और सांगली) में 13 बीपीओ/आईटीईएस इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।

भारतीय आईटी उद्योग 5.8 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कुल उद्योग कर्मचारी आधार के रूप में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी 36% है।

(ग): मंत्रालय द्वारा शुरू की गई डिजिटल कौशल विकास पहल इस प्रकार हैं:

- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए **पीएमजीदिशा (प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान)** कार्यान्वित की गई है। महाराष्ट्र में कुल 53,23,817 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें 5,83,480 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें से 38,53,643 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया जा चुका है, जिनमें 4,29,054 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार शामिल हैं।
- **फ्यूचरस्किल्स प्राइम (एफएसपी) कार्यक्रम** को नई/उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स आदि में उम्मीदवारों को कौशल/पुनः-कौशल/अप-कौशल प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। अब तक, 23.24 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और 14.08 लाख उम्मीदवारों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया है, जिनमें से 1.28 लाख नामांकन महाराष्ट्र से हैं।
- **मानवरहित विमान प्रणाली (ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकी) में मानव संसाधन विकास हेतु क्षमता निर्माण** को कार्यान्वित किया गया है ताकि मानवरहित विमान प्रणाली (यूएएस) के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण में क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास में सहयोगात्मक गतिविधियों का लाभ उठाया जा सके। अब तक, 19,626 लाभार्थियों को ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें महाराष्ट्र के 2516 लाभार्थी शामिल हैं।
- **रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिज़ाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)** में कौशल विकास की दो योजनाएँ लागू की गई हैं। अब तक 4,93,919 उम्मीदवारों को नामांकित और

प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें महाराष्ट्र के 29,325 उम्मीदवार (1677 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार) शामिल हैं।

- **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान** महाराष्ट्र राज्य में अपने स्वयं के केंद्र, अर्थात् नाइलिट औरंगाबाद और 6 मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल आधारित दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करने और डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए 692 सुविधा केंद्रों के माध्यम से कार्यरत है। पिछले 5 वर्षों में, नाइलिट ने महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रमों में 1,54,813 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से 5,341 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं।

(घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल के तहत स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का उद्देश्य सीएससी के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को ई-सेवाएँ प्रदान करना और ग्राम पंचायत स्तर तक सीएससी नेटवर्क का विस्तार करना है। सीएससी के माध्यम से 800 से अधिक सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिनमें सरकारी सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और आधार से संबंधित सेवाएँ, विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएँ, शिक्षा, टेली-मेडिसिन, यात्रा बुकिंग, उपयोगिता भुगतान शामिल हैं। यह एक अखिल भारतीय परियोजना है। सीएससी 2.0 परियोजना मार्च 2024 तक पूरी हो चुकी है। सीएससी आत्मनिर्भर और उद्यमिता मॉडल पर कार्य करते हैं।
30 जून 2025 तक, देश भर में 5,60,314 सीएससी (ग्रामीण + शहरी) कार्यरत हैं, जिनमें से 4,36,208 सीएससी ग्राम पंचायत (ग्रामीण) स्तर पर कार्यरत हैं। महाराष्ट्र राज्य में 71,761 सीएससी कार्यरत हैं, जिनमें से 53,987 सीएससी ग्राम पंचायत (ग्रामीण) स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

****